रविवार, 19 अप्रैल, 2026

www.tvbharatvarsh.in

E-PAPER

कुल पृष्ठ–08

शुभमन गिल का बड़ा बयान व्यक्तिगत फॉर्म नहीं, ट्रॉफी जीतना है लक्ष्य

Page-04

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

60 के हुए विक्रम, बर्थडे पर 'Chiyaan 63' का धमाकेदार टीज़र

Page-05

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संशोधन विधेयक पर्याप्त समर्थन न मिलने के कारण पारित नहीं हो पाया। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस और विपक्ष पर महिलाओं के साथ विश्वासघात का आरोप लगाया। इसी मुद्दे को लेकर दिल्ली में राहुल गांधी के घर के बाहर जोरदार प्रदर्शन हुआ, जिससे राजनीतिक माहौल गरमा गया।

राहुल गांधी के घर के बाहर BJP का हंगामा महिला आरक्षण बिल पर सियासी संग्राम तेज

- **राहुल गांधी के आवास के बाहर भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने महिला आरक्षण बिल पर विरोध प्रदर्शन किया।**
- **लोकसभा में 131वां संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण पास नहीं हो सका, जिससे सियासी विवाद बढ़ गया।**

नई दिल्ली में राहुल गांधी के आवास के बाहर शनिवार को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। यह विरोध लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़े संशोधन विधेयक को पर्याप्त समर्थन न मिलने को लेकर किया गया।प्रदर्शन का नेतृत्व दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने किया। इस दौरान हेमा मालिनी, मनोज तिवारी और बांसुरी स्वराज समेत कई नेता मौजूद रहे।बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने विपक्ष पर तीखा हमला करते हुए कहा कि खासकर राहुल गांधी ने देश की महिलाओं के साथ "धोखा" किया है और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अधिकार को कमजोर किया है। वहीं, हेमा मालिनी ने कहा कि बिल पास न होने से देशभर की महिलाएं निराश हैं और इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही हैं।मनोज तिवारी ने भी विपक्षी दलों—कांग्रेस, आप, टीएमसी, सपा और डीएमके—पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने महिलाओं को चुनौती दी है और इसका जवाब देश की महिलाएं देंगी।गौरतलब है कि लोकसभा में पेश 131वां संशोधन विधेयक दो-तिहाई बहुमत हासिल नहीं कर सका। इसके पक्ष में जरूरी 352 वोट नहीं मिल पाए, जबकि 230 वोट इसके खिलाफ पड़े।इस मुद्दे को लेकर संसद के अंदर और बाहर राजनीतिक माहौल गरमा गया है।इसी बीच, नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में वांछित आरोपी आदित्य आनंद को पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में तिरुचिरापल्ली रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया है। उसके ऊपर एक लाख रुपये का इनाम घोषित था।

दोहरी नागरिकता केस में FIR के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शनिवार को एक अहम फैसले में राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता मामले में एफआईआर दर्ज करने के अपने पूर्व आदेश पर रोक लगा दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ सुनवाई का मौका दिए बिना कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।दरअसल, एक दिन पहले हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश पुलिस को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया था। याचिका में आरोप लगाया गया था कि उन्होंने वर्ष 2003 में इंग्लैंड में एक कंपनी बनाते समय अपनी कथित ब्रिटिश नागरिकता की जानकारी छिपाई थी।न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने पहले अपने आदेश में कहा था कि प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है, जिसकी विस्तृत जांच जरूरी है। साथ ही राज्य सरकार को यह भी अनुमति दी गई थी कि वह इस मामले की जांच किसी केंद्रीय एजेंसी को सौंप सकती है। सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार की ओर से उप सॉलिसिटर जनरल एसबी पांडे ने संबंधित दस्तावेज पेश किए, जबकि राज्य सरकार के वकील ने भी मामले की जांच की आवश्यकता पर सहमति जताई।अब हाईकोर्ट के ताजा आदेश के बाद इस मामले में अगली सुनवाई तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की जाएगी, जिससे राहुल गांधी को फिलहाल राहत मिली है।

64 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पंजाब पुलिस ने राज्य सरकार के एंटी-ड्रग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अमृतसर में अंतरराष्ट्रीय नशा तस्करी के एक बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस ऑपरेशन में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 64.62 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है।इस मामले में अमृतसर के एसएसओसी (State Special Operation Cell) पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में लाई गई यह खेप किस जगह पहुंचाई जानी थी और इसके पीछे कौन-कौन लोग शामिल हैं।पंजाब के पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने बताया कि यह कार्रवाई राज्य सरकार के नशा-विरोधी अभियान के तहत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन में काउंटर-इंटेलिजेंस विंग और अमृतसर स्थित स्टेट स्पेशल ऑपरेशन सेल की अहम भूमिका रही।

कन्नूर बम हमला केस:

CPM के 10 कार्यकर्ताओं को 25 साल की सजा

केरल की राजनीति में लंबे समय से हिंसा और प्रतिशोध के लिए चर्चित कन्नूर से एक अहम फैसला सामने आया है। थलिपरम्बा की अदालत ने 2011 के चर्चित थिमिरी बम हमला मामले में सीपीएम के 10 कार्यकर्ताओं को 25-25 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला एडिशनल जिला एवं सत्र न्यायाधीश केएन प्रशांत ने सुनाया।अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर की जाने वाली हिंसा को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। न्यायपालिका ऐसे मामलों में सख्त रुख अपनाएगी, ताकि समाज में कानून का भय बना रहे और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा हो सके।यह मामला वर्ष 2011 का है, जब अलाकोड के पास थिमिरी क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को निशाना बनाकर बम हमला किया गया था। अभियोजन पक्ष ने अदालत में यह साबित किया कि हमला पूर्व नियोजित साजिश का हिस्सा था और इसे कन्नूर में वर्षों से चली आ रही राजनीतिक प्रतिशोध की पृष्ठभूमि में अंजाम दिया गया।कोर्ट ने मामले में उडुम्ब बिनु उर्फ टीवी बिनु सहित सभी 10 आरोपियों को दोषी ठहराया। हालांकि, अदालत ने तकनीकी आधार पर एक राहत भी दी है। 10 में से 9 दोषियों की सजाएं एक साथ चलेंगी, जिसका अर्थ है कि कागजी तौर पर भले ही सजा 25 साल की हो, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लगभग 10 साल तक जेल में रहना होगा। यह फैसला कन्नूर की हिंसक राजनीतिक परंपरा पर एक कड़ा संदेश माना जा रहा है, जहां वर्षों से वैचारिक टकराव कई बार खूनी संघर्ष में बदलता रहा है।

होर्मुज में फिर टकराव:

जहाजों पर फायरिंग और वैश्विक तेल सप्लाई पर मंडराया खतरा

मिडिल ईस्ट के बेहद संवेदनशील समुद्री मार्ग होर्मुज जलडमरूमध्य में एक बार फिर तनाव तेज हो गया है। ब्रिटिश सेना ने शनिवार को पुष्टि की कि ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स की दो गनबोट्स ने यहां से गुजर रहे एक टैंकर पर गोलीबारी की। हालांकि यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के अनुसार जहाज और उसमें सवार चालक दल पूरी तरह सुरक्षित हैं। जहाज की पहचान और गंतव्य का खुलासा नहीं किया गया है।इस घटना से पहले ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य पर सख्त नियंत्रण और प्रतिबंध दोबारा लागू करने की घोषणा की थी। यह कदम अमेरिका द्वारा ईरानी शिपिंग और बंदरगाहों पर लगाए गए प्रतिबंधों के जवाब में उठाया गया है। बीते करीब सात हफ्तों से जारी तनाव के दौरान ईरान ने अधिकांश जहाजों की आवाजाही पर रोक लगा दी है और केवल अधिकृत जहाजों को ही गुजरने की अनुमति दी जा रही है।ईरान की संयुक्त सैन्य कमान ने स्पष्ट किया है कि इस अहम जलमार्ग पर अब कड़ी सैन्य निगरानी रखी जा रही है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि जब तक अमेरिकी प्रतिबंध जारी रहेंगे, तब तक जहाजों की आवाजाही भी सीमित रहेगी। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने कहा कि अब व्यवस्था पहले की तरह हो रही है, जहां जहाजों को ईरानी नौसेना की अनुमति और टोल के बाद ही गुजरने दिया जाएगा। इस बीच अब्बास अरागची ने हाल ही में दावा किया था कि जलडमरूमध्य खुला रहेगा। उनका बयान उस समय आया जब लेबनान में इजरायल और ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के बीच 10 दिन के युद्धविराम की घोषणा हुई थी।

हिन्दी जगत महामंच

www.tvbharatvarsh.in

भारतवर्ष

सच्ची खबर, सीधे आपके लिए

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक ई-पेपर

प्रदेश का नं. 1 प्रतिष्ठित हिन्दी न्यूज़ ई-पेपर

विज्ञापन दर

साईज	विजिटिंग कार्ड	क्वाटर पेज	हाफ पेज	फुल पेज (अंदर)	फुल पेज (कवर 2 - 3)	फुल पेज (कवर 4 - अंतिम)	(फ्रंट पेज)
रेट	₹ 3000	₹ 6000	₹ 10,000	₹ 20,000	₹ 25,000	₹ 30,000	₹ 100000

8601780000

ऑस्ट्रेलिया की नई डिफेंस स्ट्रेटजी में भारत बना सबसे बड़ा साझेदार

ऑस्ट्रेलिया की डिफेंस स्ट्रेटजी 2026 में भारत को हिंद महासागर में प्रमुख सुरक्षा भागीदार बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया 888 अरब डॉलर रक्षा निवेश करेगा, आत्मनिर्भरता बढ़ाएगा और भारत के साथ सैन्य तैनाती, संयुक्त अभ्यास व समुद्री निगरानी मजबूत कर इंडो-पैसिफिक में सुरक्षा संतुलन मजबूत करेगा।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

ऑस्ट्रेलिया ने अपनी नई नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी 2026 जारी करते हुए भारत को एक प्रमुख सुरक्षा साझेदार के रूप में स्थापित किया है। इस विस्तृत रणनीतिक दस्तावेज में भारत को न केवल शीर्ष स्तर का सुरक्षा सहयोगी बताया गया है, बल्कि हिंद महासागर क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण रक्षा भागीदार भी घोषित किया गया है। ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी इस रणनीति के साथ एक "इंटीग्रेटेड इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम" भी पेश किया गया है, जो वर्ष 2036 तक की रक्षा तैयारियों का रोडमैप प्रस्तुत करता है। इस योजना के तहत ऑस्ट्रेलिया अगले दस वर्षों में कुल 888 अरब डॉलर रक्षा क्षेत्र में निवेश करेगा। इसमें से लगभग 425 अरब डॉलर नई सैन्य क्षमताओं, अत्याधुनिक हथियारों और उन्नत तकनीकों के विकास पर खर्च किए जाएंगे। इसके साथ ही 2033 तक रक्षा बजट को देश की जीडीपी के लगभग 3 प्रतिशत तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है, जो विकसित देशों के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। नई रणनीति में आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया ने रूस-यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया के मौजूदा हालातों से सबक लेते हुए यह माना है कि वैश्विक संकट की स्थिति में सप्लाई चेन बाधित हो सकती है। ऐसे में देश को अपनी सुरक्षा के लिए स्वतंत्र रूप से सक्षम होना आवश्यक है। इसी दृष्टिकोण से ऑस्ट्रेलिया लंबी दूरी की मिसाइलों, परमाणु पनडुब्बियों और एयर डिफेंस सिस्टम जैसे क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है।रणनीति का सबसे महत्वपूर्ण पहलू हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के साथ सहयोग को लेकर है। ऑस्ट्रेलिया ने पूर्वोत्तर हिंद महासागर को अपनी आर्थिक और सामरिक "लाइफलाइन" बताया है, क्योंकि इसी मार्ग से उसके ऊर्जा संसाधन—कच्चा तेल, गैस और कोयला—आवागमन करते हैं। इस क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए भारत जैसी मजबूत समुद्री शक्ति के साथ साझेदारी को अनिवार्य माना गया है। इस सहयोग के तहत ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ सैन्य उपस्थिति को नियमित बनाने का निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत तीन प्रमुख पहलुओं पर काम किया जाएगा—पहला, क्षेत्र में ऑस्ट्रेलियाई सेना की निरंतर तैनाती; दूसरा, भारतीय सशस्त्र बलों के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास और प्रशिक्षण को मजबूत करना; और तीसरा, समुद्री गतिविधियों पर कड़ी निगरानी के लिए एक सशक्त "मेरिटाइम डोमेन अवेयरनेस" प्रणाली विकसित करना।इसके अलावा, ऑस्ट्रेलिया केवल सैन्य सहयोग तक सीमित नहीं रहना चाहता, बल्कि वह भारत के साथ रक्षा उत्पादन और तकनीकी विकास के क्षेत्र में भी साझेदारी बढ़ाने की योजना बना रहा है। दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, शिक्षा और तकनीकी आदान-प्रदान को भी प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे उनकी सामरिक क्षमता और समन्वय को और सुदृढ़ किया जा सके।इस रणनीतिक दस्तावेज में क्वाड—जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका शामिल हैं—को क्षेत्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण साझेदारी के रूप में रेखांकित किया गया है।

10 रुपये के आरोप में नौकरी गई, 25 साल बाद कोर्ट से मिला इंसाफ

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

एक टिकट बुकिंग क्लर्क के खिलाफ 10 रुपये की कथित गड़बड़ी का मामला आखिरकार 25 साल बाद न्यायिक निष्कर्ष तक पहुँचा, जहां अदालत ने इसे प्रक्रियागत त्रुटियों का परिणाम बताते हुए कर्मचारी को राहत दी। घटना 4 जनवरी 2002 की है, जब नारायण नायर श्रीधाम रेलवे स्टेशन पर टिकट काउंटर पर ड्यूटी कर रहे थे। भीड़भाड़ के बीच अचानक विजिलेंस टीम ने छापा मारा। टीम के एक 'डिकॉय' यात्री ने आरोप लगाया कि नायर ने 31 रुपये के बजाय 21 रुपये लौटाए, यानी 10 रुपये कम दिए। नायर ने सफाई दी कि भीड़ के कारण गलती हो सकती है, लेकिन उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया गया और उन्हें बिना पर्याप्त सुनवाई के नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया।जांच के दौरान नायर के पास से 450 रुपये मिलने का दावा किया गया, जिसे उन्होंने अपनी बीमार पत्नी के इलाज के लिए रखा निजी पैसा बताया। साथ ही काउंटर पर मिले टिकटों के एक बंडल को भी आरोपों में शामिल किया गया, जबकि नायर ने कहा कि वह जमीन पर पड़ा था और उन्हें इसकी जानकारी नहीं थी।मामले में वित्तीय गड़बड़ी के आंकड़े भी लगातार बदलते रहे। पहले 778 रुपये अतिरिक्त होने का दावा किया गया, जो बाद में घटकर मात्र 7 रुपये रह गया।वर्ष 2026 में मामले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने पाया कि आरोपों के समर्थन में कोई स्वतंत्र गवाह नहीं था। केवल विजिलेंस टीम के सदस्य की गवाही पर पूरा मामला टिका था। अदालत ने यह भी माना कि जांच प्रक्रिया में गंभीर खामियां थीं और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया।कोर्ट ने कहा कि आरोप "संभावना के स्तर पर भी सिद्ध नहीं होते" और इतनी छोटी चूक के लिए सेवा से बर्खास्त करना अत्यधिक कठोर कदम था। इसके साथ ही अदालत ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के फैसले को बरकरार रखते हुए रेलवे की याचिका खारिज कर दी।

IAF चीफ ने भरी F-15EX में उड़ान
अमेरिका के एडवांस फाइटर का लिया जायजा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

भारतीय वायु सेना के प्रमुख एयर चीफ़ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने अमेरिका के नेवादा स्थित नेलिस एयर फ़ोर्स बेस के दौरे के दौरान अत्याधुनिक लड़ाकू विमान F-15EX Eagle II में एक परिचित (फैमिलियराइज़ेशन) उड़ान भरी। इस उड़ान में उनके साथ अमेरिकी वायु सेना के मेजर मैथ्यू बेन्सन मौजूद थे, जो 85वीं टेस्ट एवं मूल्यांकन स्क्वाड्रन के पायलट हैं। यह अनुभव भारतीय वायु सेना प्रमुख के लिए अमेरिकी वायु सेना के सबसे उन्नत फाइटर प्लेटफॉर्म में से एक को नजदीक से समझने का अवसर साबित हुआ। एफ-15EX ईगल II, अमेरिका के प्रमुख हवाई श्रेष्ठता वाले लड़ाकू विमानों का नवीनतम संस्करण है, जिसे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। नेलिस एयर फ़ोर्स बेस अमेरिकी वायु सेना के लिए उन्नत युद्ध प्रशिक्षण और ऑपरेशनल परीक्षण का प्रमुख केंद्र है। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरे के दौरान एयर चीफ को आधुनिक हवाई युद्ध, तकनीकी क्षमताओं और ऑपरेशनल रणनीतियों के बारे में विस्तृत जानकारी मिली। अपनी यात्रा के दौरान एयर चीफ़ मार्शल सिंह ने अमेरिकी वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारियों से भी मुलाकात की। इनमें ब्रिगेडियर जनरल डेविड सी. एपरसन शामिल थे। भारतीय प्रतिनिधिमंडल में एयर कमोडोर यशपाल सिंह नेगी भी मौजूद रहे। बैठकों के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को और मजबूत करने पर जोर दिया गया। विशेष रूप से संयुक्त सैन्य अभ्यासों के विस्तार, आधुनिकरण प्रयासों में समन्वय और उन्नत तकनीकों के आदान-प्रदान पर चर्चा हुई। इसके अलावा, संभावित संयुक्त अभियानों में बेहतर तालमेल और रणनीतिक साझेदारी को बढ़ाने पर भी सहमति बनी।

फ़िलिस्तीन का बड़ा आरोप,
कैदियों की हालत पर उठाए सवाल

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

फ़िलिस्तीन राज्य के दूतावास ने 'कैदी दिवस' की पूर्व संध्या पर जारी एक प्रेस बयान में फ़िलिस्तीनी कैदियों की स्थिति को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दूतावास ने इसे एक लंबे समय से चली आ रही समस्या बताते हुए कहा कि बड़े पैमाने पर गिरफ़्तारी और हिरासत का इस्तेमाल आज़ादी और आत्मनिर्णय की मांग करने वाली आवाज़ों को दबाने के लिए किया जा रहा है। बयान के अनुसार, 1967 से अब तक लगभग 7.5 लाख फ़िलिस्तीनियों को गिरफ़्तार किया जा चुका है। वहीं 7 अक्टूबर 2023 के बाद की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए दूतावास ने दावा किया कि यरूशलम सहित कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक में करीब 22,000 फ़िलिस्तीनियों को हिरासत में लिया गया है। इनमें 1,760 बच्चे, 731 से अधिक महिलाएं और 240 पत्रकार शामिल हैं। दूतावास के मुताबिक, इस अवधि में 19,954 से अधिक प्रशासनिक हिरासत आदेश जारी किए गए, जो कुल गिरफ़्तारियों का लगभग 91 प्रतिशत है। वर्तमान में करीब 9,600 फ़िलिस्तीनी इज़राइली जेलों में बंद हैं, जिनमें लगभग 350 बच्चे और 84 महिलाएं शामिल हैं, जबकि 3,532 बंदी बिना किसी आरोप या मुकदमे के हिरासत में रखे गए हैं। बयान में यह भी कहा गया कि 1967 के बाद से हिरासत में 326 कैदियों की मौत हो चुकी है और 97 शव अब तक उनके परिवारों को नहीं सौंपे गए हैं। इनमें से 86 मौतें अक्टूबर 2023 के बाद हुई बताई गई हैं। साथ ही गाज़ा के कई बंदियों के 'ज़बरन लापता' होने की भी बात कही गई है। दूतावास ने आरोप लगाया कि कैदियों को कठोर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें चिकित्सा सुविधाओं की कमी, बुनियादी अधिकारों पर प्रतिबंध, शारीरिक शोषण और कुछ मामलों में यौन हिंसा शामिल है।प्रशासनिक हिरासत की प्रथा की आलोचना करते हुए इसे औपनिवेशिक काल के कानूनों से जुड़ा बताया गया।

लेबनान हमलों पर ट्रंप का सख्त आदेश
इजराइल को रुकने की चेतावनी

टीवी भारतवर्ष अंतर्राष्ट्रीय

अमेरिका और इजराइल के संबंधों में हाल के घटनाक्रम ने एक नई जटिलता पैदा कर दी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हालिया मतभेदों ने वैश्विक कूटनीति में हलचल मचा दी है। विवाद की शुरुआत तब हुई जब ट्रंप ने अचानक घोषणा की कि इजराइल लेबनान पर किसी भी प्रकार का हवाई हमला नहीं करेगा। उन्होंने इसे अमेरिका की ओर से लागू प्रतिबंध बताते हुए सख्त लहजे में कहा कि अब इजराइल को हर हाल में रुकना होगा। यह बयान सामान्य अपील के बजाय एक स्पष्ट निर्देश के रूप में देखा गया, जिसने इजराइली नेतृत्व को चौंका दिया।बताया जा रहा है कि इस फैसले की जानकारी इजराइल को आधिकारिक तौर पर नहीं, बल्कि मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए मिली। इससे पहले अमेरिका की मध्यस्थता में इजराइल और लेबनान के बीच 10 दिन का संघर्षविराम लागू हुआ था, जिसमें इजराइल को आत्मरक्षा के तहत कार्रवाई की अनुमति दी गई थी। हालांकि, ट्रंप के ताजा बयान ने इस समझौते की व्याख्या को सीमित कर दिया। इजराइल ने तुरंत वॉशिंगटन से संपर्क कर स्थिति स्पष्ट करने की कोशिश की। अमेरिका ने बाद में कहा कि संघर्षविराम के तहत आत्मरक्षा की अनुमति है, लेकिन आक्रामक सैन्य कार्रवाई पर रोक रहेगी। ट्रंप ने अपने रुख को दोहराते हुए कहा कि इजराइल को अब बुनियादी ढांचे पर हमले बंद करने होंगे।विश्लेषकों के अनुसार, अमेरिका का यह कदम व्यापक रणनीतिक सोच का हिस्सा है। माना जा रहा है कि वॉशिंगटन इस समय ईरान के साथ संभावित समझौते की दिशा में काम कर रहा है और क्षेत्र में बढ़ता तनाव इस प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। इसके अलावा, लेबनान में नागरिक हानि को लेकर अंतरराष्ट्रीय दबाव भी बढ़ रहा है, जिससे अमेरिका अपनी छवि एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति के रूप में बनाए रखना चाहता है। इस घटनाक्रम को अमेरिका की ओर से इजराइल को दी जाने वाली पारंपरिक "खुली छूट" में बदलाव के संकेत के रूप में भी देखा जा रहा है।

संपादक की कलम से

किसी भी राष्ट्र की वास्तविक शक्ति उसकी युवा पीढ़ी में निहित होती है। युवा न केवल ऊर्जा, उत्साह और नवीन विचारों के प्रतीक होते हैं, बल्कि वे समाज में परिवर्तन लाने की क्षमता भी रखते हैं। आज भारत जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा युवाओं का है, यह शक्ति राष्ट्र निर्माण में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। युवा वर्ग में सृजनात्मकता और नवाचार की अद्भुत क्षमता होती है। वे नई तकनीकों को अपनाने में अग्रणी होते हैं और बदलते समय के साथ तेजी से तालमेल बिठा लेते हैं। यही कारण है कि आज स्टार्टअप संस्कृति, डिजिटल क्रांति और सामाजिक अभियानों में युवाओं की भागीदारी प्रमुख रूप से देखी जा रही है। यदि इस ऊर्जा को सही दिशा और अवसर मिले, तो यह देश को नई ऊँचाइयों तक पहुँचा सकती है।हालाँकि, युवा शक्ति के सामने कई चुनौतियाँ भी मौजूद हैं। बेरोज़गारी, शिक्षा की गुणवत्ता में असमानता और कौशल की कमी जैसी समस्याएँ उनके विकास में बाधा बन रही हैं। कई बार उचित मार्गदर्शन के अभाव में युवा अपनी ऊर्जा का सही उपयोग नहीं कर पाते, जिससे वे निराशा और हताशा का शिकार हो जाते हैं। इस संदर्भ में सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि वे युवाओं के लिए बेहतर अवसर और संसाधन उपलब्ध कराएँ। कौशल विकास कार्यक्रम, रोजगार के नए अवसर और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने वाली नीतियाँ इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। साथ ही, शिक्षा प्रणाली को भी ऐसा बनाना होगा, जो केवल डिग्री प्रदान करने तक सीमित न रहे, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और जीवन कौशल पर भी ध्यान दे। युवाओं को भी अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा। उन्हें केवल अधिकारों की बात करने के बजाय अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। अनुशासन, परिश्रम और सकारात्मक सोच के माध्यम से वे अपने जीवन के साथ-साथ समाज को भी बेहतर बना सकते हैं। अंततः, यह स्पष्ट है कि युवा शक्ति किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। यदि इस शक्ति का सही उपयोग किया जाए, तो यह न केवल देश के विकास को गति दे सकती है, बल्कि उसे वैश्विक स्तर पर एक सशक्त और सम्मानित राष्ट्र बना सकती है। इसलिए आवश्यक है कि हम युवाओं को सशक्त बनाएं और उन्हें उनके सपनों को साकार करने का अवसर प्रदान करें।

महिला आरक्षण विधेयक अटका

प्रियंका गांधी का सरकार पर बड़ा हमला

लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक आवश्यक दो-तिहाई बहुमत न मिलने के कारण पारित नहीं हो सका। प्रियंका गांधी ने इसे सरकार की साजिश बताते हुए लोकतंत्र की जीत कहा, जबकि सरकार ने विपक्ष पर ऐतिहासिक मौका गंवाने का आरोप लगाया।

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक के लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस महासचिव और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए इसे एक "सोची-समझी साजिश" करार दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस विधेयक के जरिए लोकतंत्र को कमजोर करने और लंबे समय तक सत्ता में बने रहने की रणनीति पर काम कर रही थी। शनिवार को नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रियंका गांधी ने कहा कि लोकसभा में इस विधेयक का पारित न होना "लोकतंत्र की बड़ी जीत" है। उन्होंने दावा किया कि विपक्ष की एकजुटता के चलते सरकार की कथित योजना विफल हो गई। उनके अनुसार, यह सिर्फ एक विधायी असफलता नहीं बल्कि संविधान और देश की जनता की जीत है। प्रियंका गांधी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह विधेयक परिसीमन (डिलिमिटेशन) से जुड़ा हुआ था, जिसके जरिए दक्षिणी और पूर्वोत्तर राज्यों की राजनीतिक ताकत को कमजोर करने की आशंका जताई जा रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार पर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी दबाव है, जो अब "स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगा है।" कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि सरकार ने महिलाओं के नाम पर राजनीति करने की कोशिश की। उनके मुताबिक, अगर विधेयक पारित हो जाता तो सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताती, और अगर असफल होता तो विपक्षी दलों को "महिला विरोधी" करार देने का प्रयास किया जाता। उन्होंने कहा, "महिलाओं का सच्चा रक्षक बनना इतना आसान नहीं है। यह सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मुद्दा नहीं होना चाहिए।" गौरतलब है कि 'संविधान (131वां) संशोधन विधेयक, 2026' लोकसभा में आवश्यक बहुमत हासिल नहीं कर सका। सदन में हुए मत विभाजन में विधेयक के पक्ष में 298 वोट पड़े, जबकि 230 सांसदों ने इसका विरोध किया। कुल 528 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया। हालांकि, संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए दो-तिहाई बहुमत यानी कम से कम 352 वोटों की आवश्यकता होती है, जो सरकार जुटाने में असफल रही। इस विधेयक का उद्देश्य लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू करना था, जिसे 2029 के आम चुनावों से प्रभावी करने का प्रस्ताव था। वहीं, सरकार ने विधेयक के पारित न होने के लिए विपक्ष को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का कहना है कि विपक्ष ने महिलाओं को अधिकार और प्रतिनिधित्व देने का एक "ऐतिहासिक अवसर" गंवा दिया है। इस घटनाक्रम के बाद महिला आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है, जहां सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपने-अपने तर्कों के साथ आमने-सामने हैं।

महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम, राजीव रंजन सिंह ने कांग्रेस को घेरा

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

लोकसभा में संविधान (131वां संशोधन) विधेयक, 2026 के पारित न हो पाने के बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी राजनीतिक बयानबाज़ी शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने विपक्ष, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी, पर महिला सशक्तिकरण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण पहल को बाधित करने का आरोप लगाया है। शनिवार को सदन में प्रतिक्रिया देते हुए सिंह ने कहा कि प्रस्तावित विधेयक का उद्देश्य संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर देश की "आधी आबादी" को न्याय दिलाना था। उनके अनुसार, यह पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम थी, जिसे विपक्ष ने रोक दिया। विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा विधेयक के पारित न होने को "लोकतंत्र की जीत" बताए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि विपक्ष एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक सुधार को झटका दे रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस का इतिहास सामाजिक बदलावों और सुधारों का विरोध करने का रहा है। राजीव रंजन सिंह ने कहा, "यह कांग्रेस का चरित्र रहा है कि वह सामाजिक परिवर्तन या क्रांति के प्रयासों को रोकती रही है। महिला आरक्षण विधेयक भी उसी का उदाहरण है।" उन्होंने यह भी दावा किया कि देश की महिला मतदाता इस मुद्दे पर विपक्ष को राजनीतिक रूप से जवाब देंगी। केंद्रीय मंत्री के अनुसार, महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रस्ताव उनके अधिकारों और प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। उन्होंने कहा कि इस विधेयक को गिराए जाने से विपक्ष भले संतुष्ट दिख रहा हो, लेकिन देश की "नारी शक्ति" इसे सकारात्मक रूप से नहीं लेगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले चुनावों में महिला मतदाता इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगी। राजीव रंजन सिंह ने कहा कि देशभर की महिलाएं इस फैसले को याद रखेंगी और इसके आधार पर अपना राजनीतिक निर्णय लेंगी। महिला आरक्षण विधेयक को लेकर यह टकराव अब राजनीतिक बहस का प्रमुख मुद्दा बन गया है, जिसमें सत्ता पक्ष इसे महिलाओं के अधिकारों का प्रश्न बता रहा है, जबकि विपक्ष अपनी अलग व्याख्या पेश कर रहा है।

TTAADC चुनाव में टिपरा मोथा की सुनामी, 28 में 24 सीटें जीतकर रचा इतिहास

टीवी भारतवर्ष राष्ट्रीय

त्रिपुरा ट्राइबल एरियाज़ ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल (TTAADC) के हालिया चुनावों में टिपरा मोथा पार्टी (TMP) ने शानदार जीत दर्ज की है। पार्टी के संस्थापक प्रद्योत बिक्रम माणिक्य देब बर्मा ने इस जीत को जनता, समुदाय और राज्य के नाम समर्पित करते हुए इसे "गरीब लोगों का जनादेश" बताया। बातचीत में बर्मा ने कहा कि यह जीत किसी एक व्यक्ति की नहीं, बल्कि पूरे समुदाय की है। उन्होंने कहा कि एक छोटी पार्टी होने के बावजूद, लोगों के अधिकारों और भविष्य के प्रति प्रतिबद्धता ने उन्हें बड़ी राजनीतिक ताकतों पर बढ़त दिलाई। बर्मा ने जोर देते हुए कहा कि यह परिणाम इस बात का संकेत है कि यदि मूल निवासियों के हितों के लिए ईमानदारी से काम किया जाए, तो संसाधनों और प्रशासनिक ताकत के बावजूद बड़ी पार्टियों को चुनौती दी जा सकती है।चुनाव परिणामों के अनुसार, TMP ने 28 में से 24 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि भारतीय जनता पार्टी को केवल 4 सीटों पर संतोष करना पड़ा। अन्य दलों—CPI(M), कांग्रेस और IPFT—को एक भी सीट नहीं मिली। TMP ने सभी 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और कुल 4,57,943 वोट प्राप्त किए, जबकि भाजपा को 2,18,072 वोट मिले।बर्मा ने कहा कि यह जनादेश पार्टी के लिए आगे की दिशा तय करने का संकेत है और उनकी प्राथमिकता मूल निवासियों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने यह भी दोहराया कि उनकी पार्टी आने वाली पीढ़ियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए संघर्ष जारी रखेगी।वहीं, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा ने चुनाव परिणामों को विनम्रता से स्वीकार करते हुए इसे सीखने का अवसर बताया। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रयासों की सराहना की और कहा कि भाजपा विकास, एकता और जनसेवा के अपने एजेंडे पर आगे भी काम करती रहेगी। साहा ने TMP को जीत की बधाई देते हुए कहा कि भाजपा और अधिक मजबूती के साथ वापसी करने का प्रयास करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि पार्टी जनता के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करेगी और भविष्य में बेहतर प्रदर्शन करेगी। इस चुनाव परिणाम को त्रिपुरा की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है, जहां एक क्षेत्रीय पार्टी ने प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए राजनीतिक समीकरणों को नई दिशा दी है।

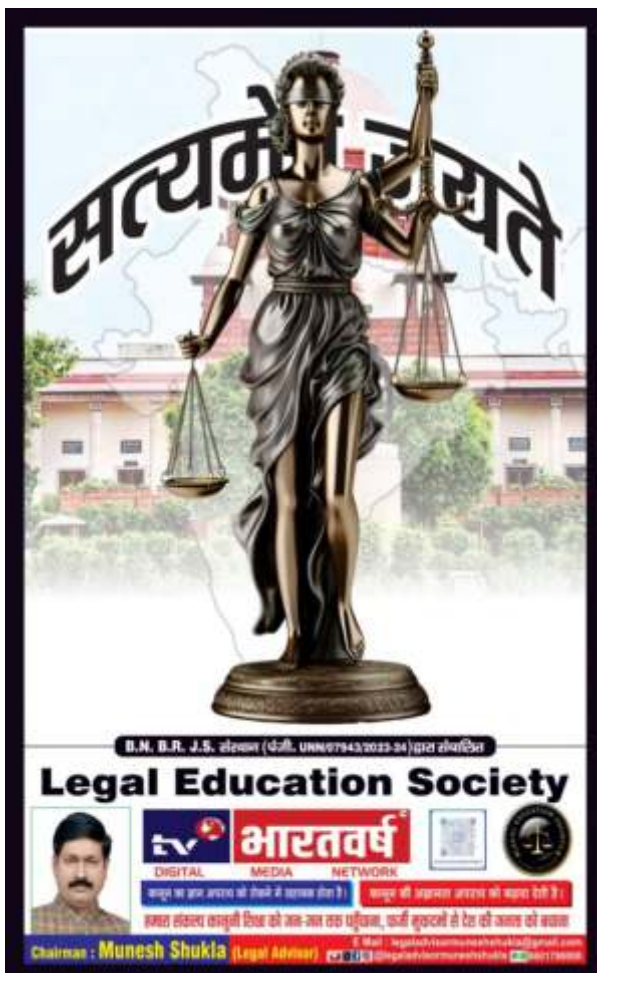

फिटनेस का व्यावसायीकरण

सेहत से ज्यादा बन गया स्टेटस सिंबल?

भारत में तेजी से विकसित हो रही फिटनेस संस्कृति अब केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह एक सामाजिक और आर्थिक बहस का विषय बनती जा रही है। विशेष रूप से बड़े शहरों में आयोजित होने वाले फिटनेस इवेंट्स, जैसे HYROX, ने लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इन आयोजनों को लेकर समाज में दो स्पष्ट धाराएँ उभरती दिखाई दे रही हैं—एक पक्ष इन्हें फिटनेस जागरूकता का सकारात्मक संकेत मानता है, जबकि दूसरा पक्ष इन्हें महंगे और दिखावटी आयोजन के रूप में देखता है। इस बहस की शुरुआत तब तेज हुई जब सोशल मीडिया उपयोगकर्ता अनकित केडिया की एक पोस्ट व्यापक रूप से वायरल हुई। उन्होंने इन आयोजनों की बढ़ती लागत पर सवाल उठाते हुए कहा कि फिटनेस निश्चित रूप से आवश्यक है, लेकिन एक दिन के इवेंट के लिए हजारों रुपये खर्च करना तर्कसंगत नहीं है। उनके अनुसार, यह प्रवृत्ति कहीं न कहीं सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदर्शित करने का माध्यम बनती जा रही है, जो फिटनेस के मूल उद्देश्य से भटकाव को दर्शाती है। वर्तमान परिदृश्य पर नजर डालें तो देश के कई महानगरों में ऐसे फिटनेस इवेंट्स की पंजीकरण फीस 3,000 से 5,000 रुपये तक पहुंच चुकी है। इसके अतिरिक्त प्रतिभागियों को बिब नंबर, टाइमिंग चिप, प्रमाण पत्र और मेडल जैसी सुविधाओं के लिए अलग से शुल्क देना पड़ता है। इस प्रकार, कुल व्यय और अधिक बढ़ जाता है, जिससे निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों की भागीदारी सीमित हो सकती है। शिक्षा और समाजशास्त्र के विशेषज्ञ इसे "फिटनेस का व्यावसायीकरण" के रूप में देखते हैं, जहां स्वास्थ्य के बजाय अनुभव और ब्रांड वैल्यू को प्राथमिकता दी जा रही है। हालांकि, इस विषय का दूसरा पक्ष भी उतना ही महत्वपूर्ण है। कई फिटनेस प्रशिक्षकों और शोधकर्ताओं का मानना है कि ऐसे आयोजन व्यक्तियों को लक्ष्य निर्धारित करने, अनुशासन विकसित करने और सामूहिक वातावरण में भागीदारी के लिए प्रेरित करते हैं। समूह में भाग लेने से प्रतिस्पर्धात्मक भावना उत्पन्न होती है, जो व्यक्ति को अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है।बेंगलुरु सहित विभिन्न शहरों के पेशेवर वर्ग का अनुभव भी इसी दिशा में संकेत करता है। उनका मानना है कि भारत में फिटनेस के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ रहा है। पहले जहां लोग खेलों को केवल दर्शक के रूप में देखते थे, वहीं अब वे सक्रिय भागीदारी को प्राथमिकता दे रहे हैं। यह परिवर्तन शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य जागरूकता के विस्तार का संकेत माना जा सकता है। ऐसे इवेंट्स पारंपरिक व्यायाम को एक संरचित प्रारूप में बदल देते हैं, जिसमें दौड़ना, वजन उठाना और अन्य गतिविधियां निर्धारित क्रम में संपन्न होती हैं। इससे प्रतिभागियों को अपनी प्रगति को मापने और सुधार करने का अवसर मिलता है।इसके बावजूद, आलोचकों का तर्क है कि वास्तविक फिटनेस निरंतर अभ्यास, संतुलित आहार और अनुशासित जीवनशैली से प्राप्त होती है, न कि महंगे आयोजनों में भाग लेने से।समग्र रूप से देखा जाए तो भारत में फिटनेस इवेंट्स का बढ़ता चलन एक ओर स्वास्थ्य जागरूकता और सहभागिता को प्रोत्साहित कर रहा है, वहीं दूसरी ओर इसके आर्थिक और सामाजिक प्रभावों पर गंभीर विचार की आवश्यकता भी प्रस्तुत कर रहा है।

भारतीय एथलेटिक्स में बवाल, कोच नवल सिंह पर दुर्व्यवहार के आरोप

पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता सुमित अंतिल ने भारतीय खेल प्राधिकरण (SAI) को दी गई शिकायत में द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच नवल सिंह पर मानसिक उत्पीड़न और मौखिक दुर्व्यवहार के गंभीर आरोप लगाए हैं। अंतिल का दावा है कि कोच का व्यवहार एथलीटों के लिए हानिकारक रहा है और उन्होंने पेशेवर सीमाएं भी पार की हैं। टोक्यो 2020 और पेरिस 2024 पैरालिंपिक में स्वर्ण पदक जीत चुके अंतिल ने आरोप लगाया कि नवल सिंह ने उन्हें और ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा को बार-बार निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि कोच ने न केवल उनके साथ बल्कि उनके परिवारों के साथ भी दुर्व्यवहार किया। अंतिल के अनुसार, समय के साथ स्थिति बिगड़ती गई, जिसके चलते उन्हें औपचारिक शिकायत दर्ज करनी पड़ी। अंतिल ने यह भी आरोप लगाया कि कोच कथित रूप से अपमानजनक टिप्पणियों की रिकॉर्डिंग बनाकर उन्हें प्रबंधन तक पहुंचाते थे, जिससे मानसिक दबाव और बढ़ता था। इस शिकायत को नीरज चोपड़ा के अलावा पैरा भाला फेंक खिलाड़ियों नवदीप सिंह और संदीप चौधरी का भी समर्थन मिला है। SAI ने पुष्टि की है कि उसे यह शिकायत प्राप्त हुई है और मामले को संबंधित महासंघ के साथ उठाया जा रहा है। हालांकि, प्राधिकरण ने स्पष्ट किया कि नवल सिंह उसके कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि वे भारतीय एथलेटिक्स महासंघ (AFI) द्वारा राष्ट्रीय कोचिंग शिविर में नियुक्त किए गए हैं।गौरतलब है कि 2015 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित नवल सिंह वर्तमान में भाला फेंक खिलाड़ी सचिन यादव को प्रशिक्षण दे रहे हैं। हालांकि, इन आरोपों पर उनकी ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अंतिल ने अधिकारियों की प्रतिक्रिया पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि यदि शीर्ष स्तर के एथलीटों की शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, तो अन्य खिलाड़ियों को न्याय मिलने की उम्मीद कैसे की जा सकती है।

रहाणे का जीत प्रतिशत 26.31% है, जो सभी कप्तानों में सबसे खराब है

शुभमन गिल का बड़ा बयान

व्यक्तिगत फॉर्म नहीं, ट्रॉफी जीतना है लक्ष्य

गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ शानदार जीत के बाद कहा कि उनके लिए व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा टीम की जीत मायने रखती है और उनका अंतिम लक्ष्य आईपीएल खिताब जीतना है। शुक्रवार को खेले गए मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को पांच विकेट से हराया। 181 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए टीम ने 19.4 ओवर में पांच विकेट खोकर जीत दर्ज की। इस जीत में कप्तान गिल की 50 गेंदों में 86 रन की शानदार पारी निर्णायक साबित हुई, जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया। मैच के बाद गिल ने कहा, "मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण टीम की जीत है। व्यक्तिगत फॉर्म उतना मायने नहीं रखता। हमारा लक्ष्य फाइनल खेलकर ट्रॉफी जीतना है।" उन्होंने आईपीएल 2023 के अपने प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि वह रिकॉर्ड अब पीछे छूट चुका है और टीम की सफलता ही प्राथमिकता है। गौरतलब है कि गिल ने आईपीएल 2023 में 890 रन बनाए थे। मौजूदा सीजन में भी वह शानदार फॉर्म में हैं और चार मैचों में 62.75 की औसत से 251 रन बनाकर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष पर पहुंच गए हैं। अपनी पारी पर प्रतिक्रिया देते हुए गिल ने कहा कि वह मैच को कुछ ओवर पहले खत्म करना चाहते थे और अंत तक टिके रहकर टीम को जीत दिलाना उनका लक्ष्य था। उन्होंने कहा, "मैं जल्दी आउट होने से निराश हूं, लेकिन उम्मीद है अगली बार अंत तक खेलूंगा।" गेंदबाजी में कगिसो रबाडा (29 रन पर तीन विकेट) और मोहम्मद सिराज (23 रन पर दो विकेट) ने नई गेंद से शानदार प्रदर्शन करते हुए केकेआर के शीर्ष क्रम को झकझोर दिया। इसके अलावा अशोक शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा ने भी अहम योगदान दिया। गिल ने रबाडा और सिराज की तारीफ करते हुए कहा कि पिच की परिस्थितियों और गर्मी को देखते हुए उन्हें अतिरिक्त ओवर दिए गए, जिसका टीम को फायदा मिला।

सरफराज अहमद बने पाकिस्तान टेस्ट टीम के हेड कोच

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मई में बांग्लादेश दौरे के लिए बड़ा फैसला लेते हुए टेस्ट टीम के नए हेड कोच के रूप में सरफराज अहमद की नियुक्ति की है। इसके साथ ही बोर्ड ने दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 16 सदस्यीय टीम की भी घोषणा कर दी है। सरफराज अहमद की कप्तानी में पाकिस्तान ने 2017 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी, जो टीम का आखिरी बड़ा आईसीसी खिताब है। उन्होंने अंडर-19 स्तर पर भी टीम को विश्व कप जिताया था। अब बतौर हेड कोच उनसे सीनियर टीम के प्रदर्शन में सुधार की उम्मीद की जा रही है। टीम की कप्तानी शान मसूद के पास ही रहेगी। चयनकर्ताओं ने चार अनकैप्ड खिलाड़ियों—अब्दुल्लाह फजल, अमाद बट, अजान आवेस और मोहम्मद गाजी गौरी—को टीम में शामिल कर युवा प्रतिभाओं को मौका दिया है। पाकिस्तान टीम 27 अप्रैल को कराची में एकत्र होगी, जहां 1 मई तक प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा। इसके बाद टीम 2 मई को बांग्लादेश के लिए रवाना होगी।पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच पहला टेस्ट मैच 8 से 12 मई के बीच ढाका के शेर-ए-बांग्ला क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 16 से 20 मई के बीच सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। इसके अलावा सहयोगी स्टाफ में असद शफीक को बल्लेबाजी कोच और उमर गुल को गेंदबाजी कोच नियुक्त किया गया है। यह कोचिंग स्टाफ फिलहाल बांग्लादेश दौरे के लिए ही नियुक्त किया गया है और आगे उनके कार्यकाल को बढ़ाने पर फैसला लिया जाएगा। इस दौरे को पाकिस्तान टीम के लिए नई शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है, जहां नए कोचिंग संयोजन के साथ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद की जा रही है।

IPL के 18 साल: अब भी मैदान में कायम दिग्गज खिलाड़ी

18 अप्रैल 2008 की तारीख फ्रेंचाइजी क्रिकेट में बहुत खास स्थान रखती है. इसी दिन इंडियन प्रीमियर लीग की शुरुआत होती है. सौरव गांगुली वो खिलाड़ी हैं, जिन्होंने IPL की सबसे पहली गेंद खेली थी. वहीं प्रवीन कुमार वो गेंदबाज थे, जिन्होंने इस लीग की सबसे पहली बॉल फेंकी थी. अब 2026 में IPL का 19वां सीजन खेला जा रहा है और ऐसे की खिलाड़ी हैं जो सबसे पहले सीजन से इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं. एमएस धोनी- एमएस धोनी ने IPL के सभी सीजन खेले हैं. चाहे अब तक चोट के कारण उन्होंने IPL 2026 में एक भी मैच नहीं खेला है, लेकिन वो अब भी CSK के एक्टिव खिलाड़ियों में से एक हैं. अपने 278 मैचों के आईपीएल करियर में उन्होंने 5,439 रन बनाए हैं.

विराट कोहली- विराट कोहली अब तक अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, जो हमेशा से IPL में एक ही टीम के लिए खेले हैं. विराट ने अपने 273 मैचों के IPL करियर में 8,907 रन बना लिए हैं. उनके नाम 8 शतक और 65 फिफ्टी हैं.

रोहित शर्मा- रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स से अपने करियर की शुरुआत की और 2011 से ही मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे हैं. 2008 से अब तक 19 सीजन में रोहित शर्मा ने 276 मैच खेलकर 7,183 रन बनाए हैं.

मनीष पांडे- IPL 2026 में मनीष पांडे कोलकाता नाइट राइडर्स टीम का हिस्सा हैं. अपने आईपीएल करियर में कुल 7 टीमों के लिए खेल चुके हैं. 174 मैचों के विशाल करियर में उन्होंने 3,942 रन बनाए हैं. वो 2008 से ही इंडियन प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं.

ऐसे भी की खिलाड़ी हैं, जो 2008 में खेले थे लेकिन सभी सीजन नहीं खेले हैं. ईशांत शर्मा, अजिंक्य रहाणे, स्वप्निल सिंह, रवींद्र जडेजा ऐसे क्रिकेटर हैं जिन्होंने 2008 में अपना आईपीएल डेब्यू कर लिया था.

इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीरें

छा गई ट्रूडो और कैटी पेरी की केमिस्ट्री

एक तरफ ट्रूडो राजनीति का बड़ा चेहरा हैं, वहीं कैटी पेरी पॉप इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं. नेट वर्थ के मामले में भी कैटी पेरी आगे हैं. 2025 के एक अनुमान के मुताबिक जहां ट्रूडो की नेट वर्थ करीब 95 मिलियन डॉलर है, वहीं कैटी पेरी की नेट वर्थ लगभग 400 मिलियन डॉलर बताई जाती है.

सच्चा प्यार किसी पहचान या पद का मोहताज नहीं होता. शायद यही वजह है कि एक तरफ राजनीति की दुनिया से आए जस्टिन ट्रूडो और दूसरी तरफ संगीत की चमकती दुनिया की स्टार कैटी पेरी, भीड़ के बीच बिल्कुल साधारण जोड़े की तरह नजर आए. इस वक्त सोशल मीडिया पर उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं. दोनों को कैलिफोर्निया के कोचेला में साथ देखा गया, जहां उनके बीच की नजदीकियों ने लोगों का ध्यान खींच लिया. कोचेला के रंगीन माहौल में दोनों एक साथ जस्टिन बीबर की परफॉर्मेंस एन्जॉय करते दिखे. जस्टिन बीबर के गानों पर झूमते हुए दोनों के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए. कैटी पेरी ने इन पलों को अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया, जिससे फैंस को उनके निजी समय की झलक मिली. वीडियो और तस्वीरों में दोनों बेहद सहज और खुश नजर आए. कभी हाथ थामे भीड़ में चलते हुए, तो कभी साथ बैठकर स्नैक्स खाते हुए. एक तस्वीर में दोनों पीछे से हाथ पकड़कर चलते दिखे, तो दूसरी में साथ बैठकर नूडल्स खाते नजर आए.

इस पूरे नजारे में सबसे खास बात थी उनकी सादगी. ट्रूडो पीछे की तरफ कैप लगाए, जींस और टी-शर्ट में नजर आए, तो पेरी शॉर्ट्स और साधारण टी-शर्ट में दिखीं. अगर कोई उन्हें पहचान न पाए, तो यह दृश्य किसी आम कपल का लग सकता था, जो पहली बार किसी कॉन्सर्ट में साथ आया हो. कैटी पेरी ने अपने सोशल मीडिया पर इन खास पलों को शेयर करते हुए पूरे वीकेंड की झलक दिखाई.

छोटे-छोटे वीडियो क्लिप्स में वह इवेंट की तैयारी, अपने जरूरी सामान और ट्रूडो के साथ बिताए समय को दिखाती नजर आईं.ट्रूडो का स्टाइल भी लोगों को पसंद आया. अगर दोनों के कनेक्शन की बात करें, तो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है. एक तरफ ट्रूडो राजनीति का बड़ा चेहरा हैं, वहीं कैटी पेरी पॉप इंडस्ट्री की सुपरस्टार हैं. नेट वर्थ के मामले में भी कैटी पेरी आगे हैं. 2025 के एक अनुमान के मुताबिक जहां ट्रूडो की नेट वर्थ करीब 95 मिलियन डॉलर है, वहीं कैटी पेरी की नेट वर्थ लगभग 400 मिलियन डॉलर बताई जाती है. ⊙

कुएं में गिरा शेर, बची जान

गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें कुएं में गिरे शेर को बाहर निकालते हुए रेस्क्यू ऑपरेशन का नाटकीय दृश्य देखा जा सकता है. गुजरात के ऊना तालुका में एक शेर के खुले खेत के कुएं में गिरने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी गुजरात के उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने शेयर की. ⊙

अब 40 हजार से भी ज्यादा कमाई

नौकरी में नहीं आया मजा तो बना डिलीवरी बॉय!

एक 22 साल के युवक ने ऑफिस की नौकरी छोड़कर डिलीवरी का काम शुरू किया और अब वह हर महीने करीब ₹40,000 कमा रहा है. उसका कहना है कि इस काम में उसे ज्यादा आजादी और कम तनाव मिलता है. आज के समय में लोग अच्छी सैलरी और आरामदायक जिंदगी के लिए ऑफिस जॉब को सबसे बेहतर मानते हैं. लेकिन हाल ही में एक 22 साल के युवक ने ऐसा फैसला लिया, जिसने सभी को हैरान कर दिया. उसने अपनी ऑफिस की नौकरी छोड़कर डिलीवरी का काम शुरू कर दिया. इस युवक का कहना है कि अब वह पहले से ज्यादा पैसा कमा रहा है और खुद

को ज्यादा संतुष्ट महसूस करता है. रिपोर्ट के मुताबिक, यह युवक पहले एक कंपनी में ऑफिस जॉब करता था. वहां उसे फिक्स सैलरी मिलती थी, लेकिन काम का दबाव ज्यादा था और समय भी तय नहीं रहता था. ⊙

कभी बर्गर मंगवाते हैं तो कभी AI से बन जाते हैं जीसस!

ये ट्रंप को हो क्या गया है?

ईरान के साथ बढ़ते तनाव, गिरती लोकप्रियता और एआई तस्वीर को लेकर उठे विवाद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में मैकडॉनल्ड्स मंगवाना महज एक साधारण घटना नहीं माना जा रहा है. इसे एक सोची-समझी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा.

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह कोई बड़ा फैसला नहीं, बल्कि व्हाइट हाउस में हुआ एक अनोखा नजारा है. सोमवार को ट्रंप ने मैकडॉनल्ड्स का अपना लंच ऑर्डर खुद दरवाजे पर जाकर लिया और वहीं मीडिया से बात करने लगे.यह घटना ऐसे वक्त हुई जब अमेरिका स्ट्रेट ऑफ होर्मुज

पर तनाव की स्थिति में था. साथ ही ट्रंप एक AI फोटो को लेकर भी चर्चा में थे, जिसमें उन्होंने खुद को जीसस क्राइस्ट के रूप में दिखाया था. बाद में उन्होंने यह पोस्ट हटा दिया. न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कोई पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन सब कुछ प्लान्ड लग रहा था. दोपहर में मीडिया को ओवल ऑफिस के बाहर बुलाया गया.

तभी एक डिलीवरी ड्राइवर आई और दरवाजा खटखटाकर 'मैकडॉनल्ड्स!' कहा. ट्रंप ने दरवाजा खोला, ऑर्डर लिया और ड्राइवर को अपने पास खड़ा कर लिया. इसके बाद उन्होंने वहीं खड़े होकर पत्रकारों से बातचीत शुरू कर दी.ड्राइवर ने भी ट्रंप की 'नो टैक्स ऑन टिप्स' नीति की तारीफ की. यह वही नीति है, जिसे ट्रंप ने 2024 चुनाव में उठाया था और बाद में कानून बनाया गया. डिलीवरी लेने के बाद ट्रंप ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी. ⊙

60 के हुए विक्रम, बर्थडे पर 'Chiyaan 63' का धमाकेदार टीज़र फैंस बोले, "अब आएगा असली तूफान!"

तमिल सिनेमा के दिग्गज अभिनेता विक्रम, जिन्हें प्रशंसक 'चियान विक्रम' के नाम से जानते हैं, ने 17 अप्रैल 2026 को अपना 60वां जन्मदिन खास अंदाज में मनाया। इस मौके को और भी यादगार बनाते हुए उनकी आगामी फिल्म 'Chiyaan 63' के निर्माताओं ने फिल्म का बहुप्रतीक्षित टीज़र जारी कर दिया, जिसने रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी। करीब एक मिनट 18 सेकंड लंबे इस टीज़र में गहरी सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर कहानी की झलक दिखाई गई है। वीडियो में विक्रम एक कुक के किरदार में नजर आ रहे हैं, लेकिन यह कोई साधारण कुक नहीं, बल्कि एक रहस्यमयी और खतरनाक अतीत वाला शख्स है। टीज़र के एक दृश्य में विक्रम अंधेरे माहौल में शांति से बीड़ी सुलगाते हुए दिखाई देते हैं, जबकि उनके आसपास अफरा-तफरी का माहौल है। यह सीन दर्शकों के बीच खासा चर्चा का विषय बन गया है और फिल्म की कहानी को लेकर उत्सुकता बढ़ा रहा है। फिल्म 'Chiyaan 63' का एक और बड़ा आकर्षण है विक्रम और निर्देशक आनंद शंकर की जोड़ी का पुनर्मिलन। दोनों ने आखिरी बार 2016 में आई सुपरहिट फिल्म इरुमुगन में साथ काम किया था। लगभग एक दशक बाद यह जोड़ी फिर से बड़े पर्दे पर वापसी कर रही है, जिससे दर्शकों की उम्मीदें और भी बढ़ गई हैं। टीज़र रिलीज के बाद से ही इसे दर्शकों का जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। यूट्यूब पर इसे कुछ ही समय में 6 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। फैंस कमेंट सेक्शन में विक्रम के लुक और फिल्म के कॉन्सेप्ट की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने विक्रम और संगीतकार संतोष नारायणन की जोड़ी को 'मैजिक' बताया है, तो कुछ ने अभिनेता के नए अवतार को 'फायर' करार दिया है। फिल्म की बात करें तो इसकी कहानी खुद आनंद शंकर ने लिखी है और निर्देशन भी वही कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण सत्या ज्योति फ़िल्म्स के बैनर तले किया जा रहा है, जबकि इसे टी.जी. त्यागराजन प्रस्तुत कर रहे हैं। फिल्म का संगीत संतोष नारायणन ने तैयार किया है, जो पहले भी कई चर्चित फिल्मों में अपनी धुनों का जादू बिखेर चुके हैं। एडिटिंग की जिम्मेदारी रेमंड डेरिक क्रास्टा को सौंपी गई है। काम के मोर्चे पर विक्रम को आखिरी बार 2025 में रिलीज हुई फिल्म वीरा धीरा सूरन: पार्ट 2 में देखा गया था, जिसमें उनके साथ सूरज वेंजारामूडु नजर आए थे। यह फिल्म अब ओटीटी प्लेटफॉर्म Prime Video पर उपलब्ध है। 'Chiyaan 63' का टीज़र यह संकेत देता है कि फिल्म में दमदार कहानी, शानदार अभिनय और सशक्त संगीत का संगम देखने को मिलेगा। ऐसे में दर्शक अब इसके ट्रेलर और रिलीज डेट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

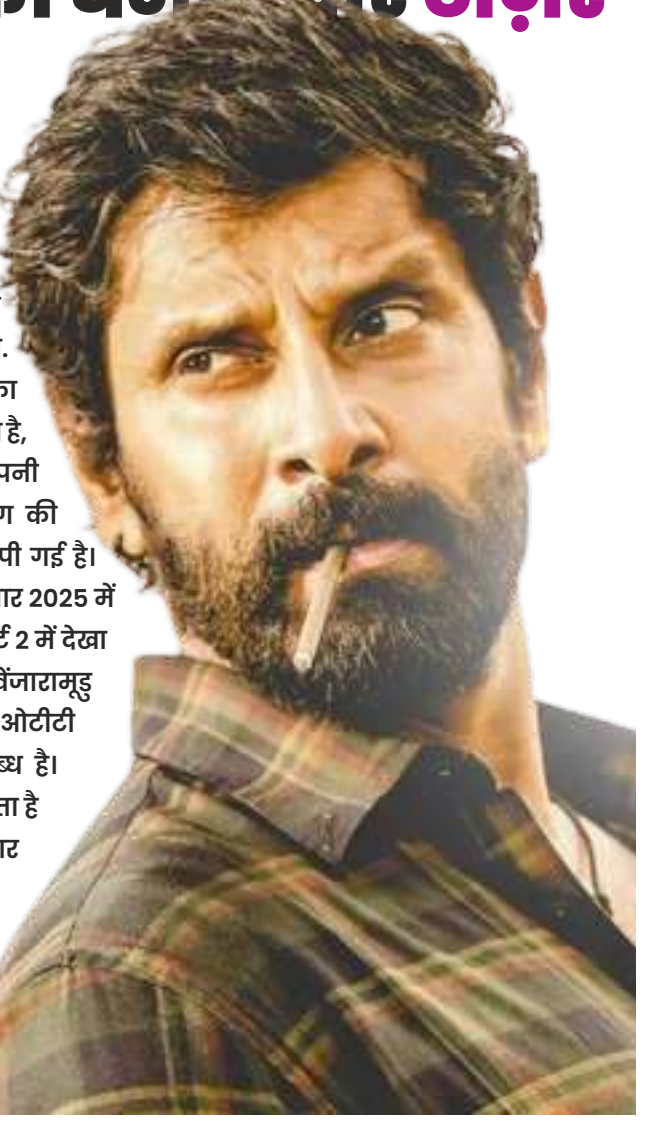

20 साल से PWD जमीन पर 1455 लोगों का अतिक्रमण कैसे?

कोर्ट ने उठाए बड़े सवाल

लखनऊ के विकासनगर अग्निकांड पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रशासन से कड़ा जवाब मांगा है। 20 साल से PWD जमीन पर अतिक्रमण, बिजली-गैस कनेक्शन और लापरवाही पर सवाल उठाए गए। कोर्ट ने पीड़ितों के लिए राहत सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, जबकि हादसे में दो बच्चों की मौत हुई।

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

राजधानी लखनऊ के विकासनगर क्षेत्र में हुए भीषण अग्निकांड को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाया है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रशासन से कई अहम सवाल पूछे हैं और विस्तृत जवाब तलब किया है। शुक्रवार को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जिलाधिकारी, नगर निगम, मुख्य चिकित्सा अधिकारी (C M O) और मुख्य अग्निशमन अधिकारी को 30 मई तक विस्तृत जवाबी शपथपत्र दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। खंडपीठ, जिसमें न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला शामिल हैं, ने राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अधिवक्ता से तीखे सवाल किए। अदालत ने पूछा कि आखिर कैसे पिछले करीब 20 वर्षों से लोक निर्माण विभाग (PWD) की लगभग चार बीघा जमीन पर 1455 लोग अतिक्रमण कर बस गए और प्रशासन इस पर निष्क्रिय बना रहा। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी जानना चाहा कि इन लोगों को बिजली और कुकिंग गैस के कनेक्शन किन कंपनियों के माध्यम से उपलब्ध कराए गए। न्यायालय ने अग्निकांड के पीड़ितों के लिए तत्काल राहत कार्य सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 15 अप्रैल को हुई इस घटना से प्रभावित लोगों को भोजन, रहने की व्यवस्था और समुचित चिकित्सा सुविधा तत्काल उपलब्ध कराई जाए। साथ ही, पीडब्ल्यूडी और प्रदेश के राहत आयुक्त को भी मामले में पक्षकार बनाने का आदेश दिया गया है। अदालत ने संकेत दिया कि पूरे प्रकरण की विस्तृत जांच कराई जा सकती है और भविष्य में सरकारी जमीनों पर अतिक्रमण रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।यह मामला अनुराग त्रिपाठी द्वारा दाखिल जनहित याचिका के माध्यम से कोर्ट के संज्ञान में आया है, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही और अवैध बसावट के मुद्दे उठाए गए हैं। गौरतलब है कि लखनऊ के पॉश इलाके विकासनगर में 15 अप्रैल की शाम करीब 5:30 बजे भीषण आग लग गई थी। आग इतनी तेजी से फैली कि 250 से अधिक झोपड़ियां जलकर राख हो गईं। हादसे के दौरान 30 से ज्यादा गैस सिलेंडरों में विस्फोट हुआ, जिससे आग ने विकराल रूप ले लिया। करीब 10 किलोमीटर दूर तक धुएं का गुबार देखा गया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए आसपास के 20 मकानों को एहतियातन खाली कराया गया। फायर ब्रिगेड की लगभग 20 गाड़ियों ने करीब पांच घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस दौरान पूरे इलाके की बिजली आपूर्ति भी बंद कर दी गई थी। घटना के बाद राजनीतिक और प्रशासनिक स्तर पर भी हलचल तेज रही। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह ने जिलाधिकारी विशाख जी. से फोन पर घटना की जानकारी ली, जबकि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। हादसे के दूसरे दिन पुलिस ने मलबे से दो मासूम बच्चियों के शव बरामद किए। दोनों बच्चियां बाराबंकी जिले के राम सनेही घाट क्षेत्र की निवासी थीं। मृतकों के परिजनों को सरकार की ओर से 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है। फिलहाल, प्रभावित परिवारों को कम्यूनिटी सेंटर और रैन बसेरों में स्थानांतरित किया गया है, जहां जिला प्रशासन द्वारा भोजन और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इस पूरे मामले ने एक बार फिर शहरी अतिक्रमण, प्रशासनिक लापरवाही और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

लखनऊ में गर्मी ने तोड़ा रिकॉर्ड, पारा 41 डिग्री तक पहुंचने की संभावना

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ में सीजन में आज पारा अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगा। सुबह से तेज धूप के साथ उमस का असर बना हुआ है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज लखनऊ का अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री के आसपास बना रहेगा। दिन में अधिकतर समय मौसम साफ रहेगा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री दर्ज किया गया। यह सामान्य से 1.3 डिग्री अधिक रहा। न्यूनतम तापमान 21.5 डिग्री रहा। अधिकतम आर्द्रता 55 फीसदी और न्यूनतम आर्द्रता 15 फीसदी दर्ज किया गया। लखनऊ में बीते 11 दिनों में 13 डिग्री तक तापमान में बढ़त दर्ज की गई है। इस बीच भीषण गर्मी के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। बीते 8 अप्रैल को लखनऊ का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा। यह सामान्य से 10.2 डिग्री कम रहा। न्यूनतम तापमान 18.8 डिग्री रहा। यह सामान्य से 0.8 डिग्री कम रहा। मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ के असर के चलते मौसम का मिजाज बदला है। इस बीच लोगों को एहतियात बरत कर घर से बाहर निकलना चाहिए। लखनऊ समेत पूरे प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक तापमान में अभी और बढ़त की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि शुष्क पछुआ हवा का असर बढ़ने और महाराष्ट्र क्षेत्र में प्रति चक्रवात के असर से पारा में बढ़त की संभावना बनी हुई है।

लखनऊ में भीषण सड़क हादसा

तेज रफ्तार कार की टक्कर से BDC सदस्य की मौत

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र स्थित बेहटा चौराहे पर शनिवार को हुए सड़क हादसे में एक बीडीसी सदस्य की दर्दनाक मौत हो गई। तेज रफ्तार इऑन कार ने सामने से आ रही बाइक को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया।मृतक की पहचान खुर्रमपुर बेहटा निवासी नौमीलाल यादव के पुत्र आशीष यादव (38) के रूप में हुई है, जो सरोजिनीनगर ब्लॉक में बीडीसी पद पर कार्यरत थे। हादसे के समय वह अपने दोस्त मनीष रावत के साथ मोटरसाइकिल से किसी कार्य के सिलसिले में कैसरबाग कोर्ट जा रहे थे। गांव से निकलते ही बेहटा चौराहे के पास तेज रफ्तार कार ने उनकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आशीष यादव सड़क पर गिरकर खून से लथपथ हो गए, जबकि उनका दोस्त मामूली रूप से घायल हुआ। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए कार चालक बृजेश पटेल (निवासी मवई पंडियाना) को दौड़ाकर पकड़ लिया और पुलिस को सूचना दी। घायल आशीष को तत्काल सरोजिनी नगर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज शुरू किया, लेकिन गंभीर चोटों के कारण उन्होंने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी पूनम और तीन बच्चों—पीहू, रुही और रौनक का रो-रोकर बुरा हाल है।ग्रामीणों के अनुसार, आशीष यादव बेहद मिलनसार और जिम्मेदार व्यक्ति थे, जो एक प्राइवेट स्कूल वैन चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। काकोरी थाना प्रभारी निरीक्षक सतीश चंद्र राठौर ने बताया कि शव का पंचायतनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। हादसे में शामिल कार (UP 32 JW 8720) को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और आरोपी चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।

सरोजनीनगर में समाधान दिवस में जमीन विवादों की बाढ़

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ के सरोजनीनगर तहसील कार्यालय में शनिवार को आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में भूमि विवाद और अवैध कब्जों से जुड़ी शिकायतों की भरमार देखने को मिली। तहसीलदार सुखबीर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे।कार्यक्रम के दौरान सबसे अधिक मामले जमीन विवाद, सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा और अनियमित प्लाटिंग से संबंधित रहे। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कई गांवों में सरकारी और पैतृक जमीनों पर अवैध कब्जे किए जा रहे हैं, जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मिर्जापुर (बेंती) निवासी राम सुमेर ने गाटा संख्या 1132 से जुड़ी शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि यह उनकी पैतृक भूमि है, जिसमें सभी भाइयों का हिस्सा है, लेकिन अभी तक राजस्व अभिलेखों में बंटवारा नहीं हुआ है। इसी बीच उनके चचेरे भाई गया प्रसाद सहित अन्य लोग जमीन पर अवैध निर्माण करा रहे हैं। उन्होंने निर्माण कार्य रोकने की मांग की। हरिहरपुर के भाजपा बूथ अध्यक्ष मुकेश कुमार यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी अभिलेखों में ऊसर, बंजर और तालाब के रूप में दर्ज जमीन पर अवैध प्लाटिंग कर उसे बेचा जा रहा है। उन्होंने तत्काल कार्रवाई की मांग की।इसी तरह सिविल कोर्ट से जुड़े संदीप सिंह ने ग्राम सभा बिजनौर की गाटा संख्या 956 पर अवैध कब्जे और प्लाटिंग का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में पहले मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। खटोला निवासी राजेश कुमार ने भी रतौली गांव की पशु मरघट भूमि (खसरा संख्या 144) पर प्रॉपर्टी डीलरों द्वारा कब्जे की शिकायत की और जमीन को कब्जा मुक्त कराने की मांग की।

लखनऊ पुलिस का बड़ा खुलासा

1180 बोरी पीओपी धोखाधड़ी का पर्दाफाश

टीवी भारतवर्ष लखनऊ

लखनऊ पुलिस ने 1180 बोरी पीओपी (सकरनी ब्रांड) की धोखाधड़ी का खुलासा किया है। इस मामले में तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से पूरी 1180 बोरी पीओपी, दो मोटरसाइकिल और चार मोबाइल फोन बरामद किए हैं। यह कार्रवाई मात्र 72 घंटे के भीतर की गई। पुलिस के अनुसार, यह धोखाधड़ी तब हुई जब राजस्थान से बाराबंकी जा रहे एक ट्रक को रास्ते में फोन कॉल कर रोका गया। आरोपियों ने खुद को फर्जी फर्म मालिक बताया और ट्रक चालक को गोसाईंगंज क्षेत्र में माल उतरवाने का झांसा दिया। इसके बाद, नकली मुंशी भेजने की बात कहकर चालक को विश्वास में लिया गया। कुछ ही देर बाद, तीन आरोपी डाला और ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने ट्रक से पीओपी की बोरियां उतरवाईं और उन्हें ग्राम कबीरपुर स्थित एक किराए के कमरे में छिपा दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब बाराबंकी स्थित असली फर्म से संपर्क किया गया और पता चला कि माल वहां पहुंचा ही नहीं है। शक होने पर ट्रक चालक ने थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। प्रभारी निरीक्षक डी.के. सिंह के नेतृत्व में दो टीमों का गठन किया गया। पुलिस ने 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और सर्विलांस की मदद से आरोपियों तक पहुंची। 17 अप्रैल को पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के बेली अंडरपास के पास से तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया।

लखनऊ एयरपोर्ट पर बड़ी कार्रवाई, 14.5 करोड़ की ड्रग्स के साथ यात्री गिरफ्तार

लखनऊ स्थित चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर शुक्रवार सुबह एक बड़ी मादक पदार्थ तस्करी का मामला सामने आया, जहां सुरक्षा एजेंसियों ने एक अंतरराष्ट्रीय यात्री को भारी मात्रा में हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) के साथ गिरफ्तार किया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का वजन 14.504 किलोग्राम बताया गया है, जिसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 14.50 करोड़ रुपये आंकी गई है।जानकारी के अनुसार, यह कार्रवाई खुफिया सूचना के आधार पर एयर इंटेलिजेंस यूनिट (AIU) और कस्टम क्लीयरेंस सिक्योरिटी इंटरनेशनल (CCSI) की संयुक्त टीम द्वारा की गई। यात्री ओमान एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या WY-265 से बैंकॉक से मस्कट होते हुए शुक्रवार सुबह करीब 8:20 बजे लखनऊ पहुंचा था। जैसे ही वह ग्रीन चैनल से गुजर रहा था, उसके संदिग्ध व्यवहार को देखते हुए अधिकारियों ने उसे रोक लिया और उसके सामान की विस्तृत जांच शुरू की।जांच के दौरान उसके बैग से 29 पारदर्शी वैक्यूम-पैक पाउच बरामद हुए, जिनमें हरे रंग का फूलनुमा पदार्थ भरा हुआ था। प्रारंभिक परीक्षण में यह पदार्थ गांजा/मारिजुआना यानी हाइड्रोपोनिक वीड पाया गया। यह मादक पदार्थ विशेष रूप से नियंत्रित वातावरण में उगाया जाता है और इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी मांग रहती है, जिसके कारण इसकी कीमत करोड़ों में होती है। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई करते हुए पूरे मादक पदार्थ को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 की धारा 43 के तहत जब्त कर लिया। इसके बाद आरोपी यात्री को हिरासत में लेकर गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, यह मामला अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क से जुड़ा हो सकता है। प्रारंभिक जांच में यह आशंका जताई जा रही है कि यात्री किसी संगठित गिरोह का हिस्सा हो सकता है, जो बैंकॉक और अन्य दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से भारत में मादक पदार्थों की तस्करी करता है। फिलहाल, आरोपी से पूछताछ जारी है और उसके संपर्कों, यात्रा मार्ग तथा वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की जा रही है।

स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर भड़की कांग्रेस

गरीबों पर बढ़ रहा आर्थिक बोझ

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव में युवा कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक शिवहरे ने केंद्र सरकार की नीतियों पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने स्मार्ट मीटर, एलपीजी की किल्लत और यूएस ट्रेड डील जैसे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरा। यह बयान उन्होंने शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान दिया। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुरेंद्र कुशवाहा सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे।प्रेसवार्ता में संगठनात्मक गतिविधियों की जानकारी देते हुए दीपक शिवहरे ने बताया कि हाल ही में 'विद आईवाईसी' अभियान के तहत युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के कार्यों का 90 दिनों तक मूल्यांकन किया गया था। इसी मूल्यांकन के आधार पर सैफ को उन्नाव का नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि संगठन में जिम्मेदारियां केवल मेहनत और सक्रियता के आधार पर दी जा रही हैं, जिससे संगठन को मजबूत किया जा सकेकेंद्र सरकार की नीतियों पर हमला बोलते हुए शिवहरे ने यूएस ट्रेड डील को किसान विरोधी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि यह समझौता विदेशी कंपनियों को लाभ पहुंचाने के लिए तैयार किया गया है, जबकि इसका सीधा नुकसान देश के किसानों और छोटे व्यापारियों को उठाना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियां

उद्योगपतियों के हितों को प्राथमिकता दे रही हैं, जिससे आम जनता प्रभावित हो रही है।स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटरों के मुद्दे पर भी उन्होंने कड़ा विरोध जताया। उनका कहना था कि पहले से ही आर्थिक तंगी झेल रहे गरीब और मजदूर वर्ग पर यह व्यवस्था अतिरिक्त बोझ डाल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि बैलेंस खत्म होते ही बिजली कट जाने से लोगों के दैनिक जीवन, खासकर बच्चों की पढ़ाई पर गंभीर असर पड़ रहा है। उन्होंने मांग की कि इस व्यवस्था को तत्काल वापस लिया जाए या फिर इसे पोस्टपेड प्रणाली के तहत लागू किया जाए। एलपीजी सिलेंडर की किल्लत और कालाबाजारी को लेकर भी उन्होंने सरकार की आलोचना की। शिवहरे ने कहा कि गैस एजेंसियों पर उचित नियंत्रण न होने के कारण बाजार में कालाबाजारी बढ़ रही है। कई स्थानों पर सिलेंडर निर्धारित मूल्य से 1000 से 2000 रुपये अधिक कीमत पर बेचे जा रहे हैं, जिससे आम जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और लोग दोबारा चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हो रहे हैं। उन्होंने राजनीतिक विरोध के नाम पर झंडा जलाने जैसी घटनाओं को भी गलत बताया और कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के प्रतीकों का सम्मान होना चाहिए क्योंकि उनसे लाखों लोगों की भावनाएं जुड़ी होती हैं। उन्होंने कहा कि विरोध नीतियों का होना चाहिए, न कि प्रतीकों का अपमान। महिला आरक्षण बिल पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 33 प्रतिशत आरक्षण के पक्ष में है, लेकिन इसमें ओबीसी और एससी वर्ग की महिलाओं को उचित प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्तमान स्वरूप में यह बिल सभी वर्गों को समान न्याय नहीं देता।

सबमर्सिबल मोटर के करंट से किसान की मौत

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के अचलगंज थाना क्षेत्र के शिवपुरी गांव में एक किसान की समरसेबल मोटर की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान 35 वर्षीय दीपू वर्मा पुत्र भोला वर्मा के रूप में हुई है। घटना शुक्रवार देर रात की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, दीपू वर्मा शुक्रवार देर रात अपने घर के पास लगे समरसेबल मोटर के पास किसी काम से गए थे। इसी दौरान वह मोटर में प्रवाहित करंट की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। परिजनों को रात में इस घटना की जानकारी नहीं हो सकी। शनिवार सुबह जब परिवार के लोग जागे और दीपू को घर में नहीं पाया, तो उनकी तलाश शुरू की गई। खोजबीन के दौरान दीपू घर के पास समरसेबल मोटर के पास मृत अवस्था में मिले। घटना की सूचना मिलते ही अचलगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पंचनामा की कार्रवाई की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। अचलगंज इंस्पेक्टर बृजेश शुक्ला ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। मृतक दीपू वर्मा एक मेहनती किसान थे और खेती-किसानी कर अपने परिवार का भरण-पोषण करते थे। उनके परिवार में 11 वर्षीय बेटी दिव्या है।

उन्नाव जिला अस्पताल में सुरक्षा गार्ड पर आरोप

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव के जिला अस्पताल में एक सुरक्षा गार्ड पर भर्ती युवती से छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगा है। यह घटना सदर कोतवाली क्षेत्र स्थित अस्पताल के वार्ड नंबर 2 में देर रात हुई, जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जानकारी के अनुसार, बारासगवर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक युवती को थ्रेसर मशीन से गेहूं कटाई के दौरान चोट लग गई थी। उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद शुक्रवार रात उसे इमरजेंसी से वार्ड नंबर 2 में भर्ती किया था। आरोप है कि देर रात ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड वार्ड में पहुंचा और उसने पहले वार्ड की सभी लाइटें बंद कर दीं। इसके बाद वह युवती के बिस्तर के पास गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा। बताया जा रहा है कि गार्ड ने स्वास्थ्य का हाल जानने के बहाने युवती के करीब जाने की कोशिश की। घटना के समय युवती की मां भी वहीं बिस्तर के नीचे सो रही थी। युवती ने विरोध करते हुए जोर से चिल्लाना शुरू किया, जिससे वार्ड में अफरा-तफरी मच गई। शोर सुनकर आसपास के मरीज और अस्पताल स्टाफ मौके पर पहुंचे, जिसके बाद यह मामला सामने आया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और आरोपी सुरक्षा गार्ड को हिरासत में ले लिया। पुलिस इस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। इस घटना ने जिला अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, खासकर महिला मरीजों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। सदर कोतवाली प्रभारी सी.के. मिश्रा ने बताया कि प्रकरण की गंभीरता से जांच की जा रही है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

उन्नाव नगर पालिका की बड़ी पहल

शुरू हुई 'ई-नगर सेवा' डिजिटल व्यवस्था

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव नगर पालिका परिषद ने शहरवासियों को बड़ी राहत देते हुए डिजिटल सेवा की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। नगर पालिका अध्यक्ष श्वेता मिश्रा ने 'ई-नगर सेवा' की शुरुआत की घोषणा की है, जिसके तहत अब नागरिक घर बैठे ही ऑनलाइन टैक्स जमा कर सकेंगे। अध्यक्ष ने बताया कि पिछले ढाई से तीन वर्षों से लोगों को टैक्स जमा करने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खासकर गर्मी के मौसम में नगर पालिका कार्यालय में लंबी कतारें लगती थीं, जिससे लोगों का समय और ऊर्जा दोनों बर्बाद होती थी। इस नई व्यवस्था के लागू होने के बाद अब नागरिक 24 घंटे, कहीं से भी अपने मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से टैक्स भुगतान कर सकेंगे। भुगतान होते ही रसीद सीधे मोबाइल पर उपलब्ध हो जाएगी।उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और सुविधाजनक होगी, जिससे लोगों को कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। पहले जो सुविधाएं केवल कार्यालय में जाकर मिलती थीं, अब वही सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि कार्यप्रणाली भी अधिक प्रभावी बनेगी। नगर पालिका ने नामांतरण (म्यूटेशन) प्रक्रिया में भी बड़ा सुधार किया है। पहले इस प्रक्रिया में महीनों और कई बार सालों तक देरी की शिकायतें आती थीं, लेकिन अब इसे अनिवार्य रूप से 45 दिनों के भीतर पूरा करना होगा। यदि निर्धारित समय में कार्य पूरा नहीं होता है तो मामला स्वतः मुख्यमंत्री पोर्टल पर भेज दिया जाएगा और संबंधित कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। नगर पालिका अध्यक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि 'ई-नगर सेवा' व्यवस्था वर्षभर 365 दिन उपलब्ध रहेगी, जिससे नागरिक किसी भी समय इसका लाभ उठा सकेंगे।इसके साथ ही टैक्स भुगतान पर छूट की भी घोषणा की गई है। 15 मई तक टैक्स जमा करने पर 20 प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि 15 नवंबर तक भुगतान करने पर 10 प्रतिशत की छूट का लाभ दिया जाएगा। नगर पालिका की इस पहल को शहर में डिजिटल प्रशासन को बढ़ावा देने और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। स्थानीय नागरिकों ने भी इस सुविधा का स्वागत किया है और उम्मीद जताई है कि इससे उनकी समस्याओं में काफी कमी आएगी तथा सेवाएं तेजी से उपलब्ध होंगी।

अस्पताल में सीएमएस ही गायब, डॉक्टरों की भारी अनुपस्थिति से मचा हड़कंप

टीवी भारतवर्ष उन्नाव

उन्नाव जिले के मौरावां स्थित 100 बेड अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की गंभीर खामियां सामने आई हैं। पुरवा के एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव ने शनिवार को अस्पताल का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई अनियमितताएं और कर्मचारियों की अनुपस्थिति उजागर हुई। निरीक्षण के दौरान अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक (सीएमएस) मौके पर मौजूद नहीं पाए गए, जिससे प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक की ड्यूटी में तैनात तीन डॉक्टरों में से केवल डॉक्टर कटियार ही अस्पताल में उपस्थित मिले। डॉक्टर नेहा और डॉक्टर मनीषा ड्यूटी से अनुपस्थित पाई गईंडॉक्टरों की कमी के कारण स्थिति और भी खराब दिखाई दी, जहां एक ही डॉक्टर को ओपीडी और इमरजेंसी दोनों विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही थी। इससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा था और अस्पताल में अव्यवस्था का माहौल बना रहा। मरीजों और उनके तीमारदारों ने भी इलाज में देरी और चिकित्सकीय सेवाओं की कमी को लेकर नाराजगी जताई। एसडीएम ने निरीक्षण के दौरान पैथोलॉजी, फार्मेसी, ओपीडी और इमरजेंसी वार्ड का भी विस्तार से जायजा लिया। इन सभी विभागों में कई कमियां पाई गईं, जिनमें संसाधनों की कमी, स्टाफ की अनुपस्थिति और प्रबंधन में लापरवाही प्रमुख रही। निरीक्षण के दौरान यह भी सामने आया कि अस्पताल में मौजूद मरीजों को आवश्यक सुविधाएं समय पर नहीं मिल रही थीं, जिससे उनकी परेशानी बढ़ गई थी। कई मरीजों ने शिकायत की कि डॉक्टरों की अनुपस्थिति के कारण उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। एसडीएम प्रमेश श्रीवास्तव ने स्थिति को गंभीर मानते हुए पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट जिलाधिकारी को भेज दी है। उन्होंने संबंधित स्वास्थ्य अधिकारियों को तत्काल अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार करने और अनुपस्थित कर्मचारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक स्तर पर इस औचक निरीक्षण के बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार और जवाबदेही तय करने के लिए कड़े

उन्नाव के गांवों में पानी संकट बरकरार, आजादी के 70 साल बाद भी बुनियादी सुविधा से वंचित

उन्नाव के सदर विधानसभा क्षेत्र के करीमाबाद, चंदन खेड़ा और अमलोना गांवों में पीने के पानी का गंभीर संकट है। आजादी के 70 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन गांवों के लोग बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। तीनों गांवों के ग्रामीण अपनी प्यास बुझाने के लिए केवल एक हैंडपंप पर निर्भर हैं। ग्रामीणों सुमेर, मुनेश, रंजीत और महेश के अनुसार, गांव के अधिकांश हैंडपंपों का पानी दूषित है। यह पानी न तो पीने योग्य है और न ही खाना बनाने के काम आता है। इस कारण लोगों को रोजाना कई किलोमीटर दूर जाकर पानी लाना पड़ता है। महिलाओं और बच्चों को इस समस्या का सबसे अधिक सामना करना पड़ता है, जिनका दिन का बड़ा हिस्सा पानी लाने में ही बीत जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह समस्या वर्षों पुरानी है और इसका कोई स्थायी समाधान नहीं हुआ है। हर चुनाव में जनप्रतिनिधि बड़े वादे करते हैं, लेकिन चुनाव के बाद वे पूरे नहीं होते। पानी के संकट के साथ-साथ बाढ़ की समस्या भी इन गांवों के लिए एक बड़ी चुनौती है, जिससे स्थिति और बिगड़ जाती है। सरकार की अमृत जल योजना के तहत गांवों में पाइपलाइन बिछाई गई है। हालांकि, अब तक घरों तक पानी की आपूर्ति शुरू नहीं हुई है। इससे ग्रामीणों में निराशा और नाराजगी है। उनका कहना है कि पाइपलाइन बिछने के बावजूद पानी न मिलने से योजना का कोई लाभ नहीं है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द पानी की समस्या का समाधान करने की मांग की है। उनका कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। 2027 के विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही ग्रामीणों की उम्मीदें एक बार फिर जगी हैं।

तीन श्रेणियों में नई दरें लागू

योगी आदित्यनाथ सरकार का बड़ा फैसला

यह निर्णय उस समय लिया गया जब श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर गतिरोध की स्थिति बनी और औद्योगिक गतिविधियां प्रभावित होने लगीं। श्रमिकों का कहना था कि बढ़ती महंगाई और किराए के दबाव के कारण जीवनयापन कठिन हो गया है, जबकि नियोक्ताओं ने वैश्विक आर्थिक दबाव, बढ़ती लागत और आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं का हवाला दिया।

नोएडा और ग्रेटर नोएडा में हालिया घटनाक्रम के बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने बड़ा हस्तक्षेप करते हुए न्यूनतम मजदूरी दरों में संशोधन का निर्णय लिया। सरकार के निर्णय पर प्रदेश की राज्यपाल ने भी अपनी मुहर लगाते हुए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित नई न्यूनतम मजदूरी दरें कानूनी रूप से प्रभावी हो गई हैं। अब यह पूरे प्रदेश में बाध्यकारी रूप से लागू होंगी। उल्लेखनीय है कि घटनाक्रम के बाद श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच वेतन वृद्धि को लेकर गतिरोध खत्म करने और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने उच्च स्तरीय समिति गठित की थी, जिसने अपनी सिफारिश में तीन श्रेणियों में वेतन की दरें निर्धारित की हैं। इसके आधार पर राज्य सरकार ने अंतरिम राहत के रूप में नई मजदूरी दरें लागू करते हुए प्रदेश को तीन श्रेणियों में विभाजित किया है, जिससे क्षेत्रीय परिस्थितियों और जीवन-यापन की लागत के अनुसार संतुलित व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। समिति की सिफारिशों के आधार पर प्रदेश को तीन श्रेणियों में बांटा गया। प्रथम श्रेणी में गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद को रखा गया, जहां जीवन-यापन की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। यहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,690 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 15,059 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,868 रुपये मासिक न्यूनतम मजदूरी तय की गई है। द्वितीय श्रेणी में नगर निगम वाले अन्य जिलों को शामिल किया गया है, जहां अकुशल श्रमिकों के लिए 13,006 रुपये, अर्द्धकुशल के लिए 14,306 रुपये और कुशल श्रमिकों के लिए 16,025 रुपये निर्धारित किए गए हैं। वहीं तृतीय श्रेणी में शेष जिलों को रखा गया है, जहां मजदूरी दरें क्रमशः 12,356 रुपये, 13,590 रुपये और 15,224 रुपये तय की गई हैं। इन सभी दरों में मूल वेतन के साथ परिवर्तनीय महंगाई भत्ता (वीडीए) शामिल है। दरअसल, वर्ष 2019 और 2024 में प्रस्तावित मजदूरी संशोधन लागू नहीं हो पाए थे, जिसके चलते यह अंतर बढ़ता गया। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर लंबित पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। सरकार का कहना है कि यह निर्णय न केवल श्रमिकों को राहत देने के लिए है, बल्कि औद्योगिक शांति बनाए रखने और उत्पादन चक्र को सुचारू रखने के लिए भी आवश्यक है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि नई दरें लागू होने के बाद श्रमिकों के हितों में किसी प्रकार की कटौती या अनियमितता पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

वाराणसी के नहिया गांव में भगवा-नीले झंडे विवाद से भड़का हिंसक बवाल

वाराणसी के नेहिया गांव में भगवा और नीले झंडे लगाने के विवाद में जमकर बवाल हुआ। शुक्रवार को बवाल ने हिंसक रुप ले लिया। पत्थरबाजी में ACP विदुष सक्सेना, इंस्पेक्टर, दरोगा समेत 7 पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने लाठी पटककर उपद्रवियों को खदेड़ा। गोसाईंपुर चौकी इंचार्ज विपिन पांडेय की तहरीर पर 11 नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ FIR दर्ज कराई है। अब आरोपियों की तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। शनिवार सुबह भी पीएसी के साथ 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात है। नहिया की दलित बस्तियों में बूटों की धमक गूंज रही है। गांव में सन्नाटा पसरा है। गिरफ्तारी के डर से नहिया गांव में दलित बस्ती के ज्यादातर युवक घर छोड़कर भाग गए हैं। पुलिस ने गांव के गेट पर सीसीटीवी लगवा दिया है। जबकि 6 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वाराणसी मुख्यालय से 30k m दूर बाबतपुर-चौबेपुर मार्ग पर नहिया गांव में प्रवेश करने के लिए गेट बनाया गया है। प्रवेश द्वार पर 'बाबा बटुक भैरव धाम' लिखा हुआ है। वहीं गांव में हाईवे से करीब आधा किलोमीटर दूरी पर संत रविदास मंदिर है। जबकि हाईवे से करीब करीब 800 मीटर दूरी पर बाबा बटुक भैरव का मंदिर है। हिंदू संगठनों का दावा है कि गांव के प्रवेश गेट पर जब से निर्माण हुआ है तब से रामनवमी पर भगवा झंडा लगाया जाता रहा है। इस साल भी झंडा लगा था लेकिन 14 अप्रैल को डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती के जुलूस के दौरान किसी ने उसे हटाकर वहां डॉ. भीमराव अंबेडकर का झंडा लगा दिया। आरोप है कि 15 अप्रैल को इसकी सूचना मिलने के बाद शाम या रात के समय हिंदू धर्म संगठन के लोगों ने उस झंडे को तोड़कर हटा दिया। अगले दिन यानी 16 अप्रैल को इस मामले की जानकारी मिलने के बाद काफी संख्या में दलित समुदाय के लोग पहुंच गए। उसके बाद लोग नारेबाजी करने लगे। दलित समुदाय के लोगों ने कहा- जब गेट पर एक विशेष झंडा लग सकता है, तो संत रविदास और बाबा साहेब का झंडा क्यों नहीं? वहीं दूसरा पक्ष इसे मंदिर का प्रवेश द्वार बताकर अपनी पुरानी परंपरा पर अड़ा रहा। इसी बात को लेकर तनाव हुआ और गुरुवार यानी 16 अप्रैल को डेढ़ घंटे हाईवे जाम रहा।

राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर आदेश पर फिलहाल रोक, अगली सुनवाई 20 अप्रैल को

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने कथित दोहरी नागरिकता मामले में कांग्रेस नेता एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने संबंधी अपने पूर्व आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। यह आदेश शनिवार को हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी विस्तृत निर्णय में सामने आया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सहित केंद्र और राज्य सरकार के अधिवक्ताओं से यह पूछा गया था कि क्या इस मामले में विपक्षी संख्या एक यानी राहुल गांधी को नोटिस जारी किया जाना आवश्यक है। इस पर दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अदालत को बताया कि नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है, जिसके बाद ओपन कोर्ट में एफआईआर दर्ज करने का आदेश मौखिक रूप से पारित कर दिया गया था। हालांकि, आदेश टाइप होने और उस पर हस्ताक्षर होने से पहले न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने एक महत्वपूर्ण विधिक बिंदु पर पुनर्विचार किया। उन्होंने पाया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने वर्ष 2014 के एक फैसले में यह स्पष्ट किया था कि एफआईआर दर्ज करने की मांग वाली याचिकाओं के खारिज होने पर पुनरीक्षण याचिका ही स्वीकार्य होती है और ऐसे मामलों में प्रस्तावित अभियुक्त को नोटिस जारी करना अनिवार्य है। इसी विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए न्यायालय ने कहा कि बिना संबंधित पक्ष को नोटिस दिए मामले का निपटारा करना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर पूर्व में दिए गए एफआईआर दर्ज करने के आदेश पर रोक लगा दी गई और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 20 अप्रैल 2026 तय की गई हैयह मामला कर्नाटक निवासी याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर याचिका से संबंधित है, जिसमें राहुल गांधी पर दोहरी नागरिकता रखने का आरोप लगाया गया है। याचिका में उन पर भारतीय न्याय संहिता, आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत गंभीर आरोप लगाए गए हैं और विस्तृत जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की प्रारंभिक सुनवाई रायबरेली के विशेष न्यायालय में हुई थी, जहां से इसे खारिज कर दिया गया था। इसके बाद 17 दिसंबर 2025 को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने मामले को रायबरेली से लखनऊ स्थानांतरित किया था।

सपा-कांग्रेस के खिलाफ नारेबाजी, झंडे जलाकर जताया विरोध

लखनऊ में राजनीतिक माहौल उस समय गरमा गया जब भाजपा नेता और उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव ने विधानसभा भवन के सामने समर्थकों के साथ प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी (सपा) और कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और दोनों दलों के झंडे जलाकर विरोध जताया। अपर्णा यादव ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल महिला आरक्षण के मुद्दे पर सिर्फ दिखावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस कभी नहीं चाहते कि आम घरों की महिलाएं संसद तक पहुंचें और ये दल केवल परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। वहीं अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा को प्रदर्शन के लिए "कम से कम 12 महिलाएं" तो भेजनी चाहिए थीं। इस पूरे घटनाक्रम से लखनऊ की राजनीति में तनाव और बढ़ गया है।